



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625]
No. 2625]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2017/भाद्र 21, 1939
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

विषय: काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 में संशोधन।

का.आ. 3000(अ).—टी.एन. गोदावर्मेन यिरूभलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के संकल्प के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के आधार पर भारत सरकार ने दिशानिर्देशों को निम्न प्रकार से संशोधित करने का विनिश्चय किया है:—

1. दिशानिर्देशों के पैरा —2(1) के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:

(i) इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) 'औद्योगिक सम्पदा' से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।
- (ख) 'लाइसेंस' से किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिसूचित नियमों के अधीन दिया गया लाइसेंस अभिप्रेत है।

- (ग) 'प्रधान मुख्य वन संरक्षक' से किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का वन अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसे किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का पद विद्यमान नहीं है, में वन विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित अधिकारी भी शामिल है।
- (घ) 'गोल लट्टा' से अपने प्राकृतिक रूप में काष्ठ का ऐसा लट्टा अभिप्रेत है जिसका छाल के नीचे का मध्य घेरा तीस सेन्टीमीटर का या उससे अधिक हो और इसमें छाल हटाये जाने के पश्चात ऐसा गोल लट्टा भी शामिल है जिसकी सतह की इसके परिवहन और/या भंडारण में सुविधा के प्रयोजनार्थ इसके क्रॉस सेक्शन को वर्गाकार या लगभग वर्गाकार बनाने के लिए हाथ से या किसी बैंड साँ या अन्य किसी मशीन या उपस्कर द्वारा छिलाई की गई है।
- (ङ.) 'बारा मिल' से गोल लट्टों को चीरे हुए काष्ठ में परिवर्तित करने के लिए किसी नियत संरचना या परिसर में स्थित संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है।
- (च) 'चीरी हुई इमारती लकड़ी' से किसी गोल लट्टे से प्राप्त शहतीर, कड़ी, तख्ते, पट्टे और अन्य ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं।
- (छ) 'राज्य स्तरीय समिति' से राज्य सरकार द्वारा इन दिशानिर्देशों के पैरा 3(2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।
- (ज) 'काष्ठ आधारित उद्योग' से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जो काष्ठ को कच्चे माल के रूप में संसाधित करता है (आरा मिल/वेनियर/प्लाइवुड या चंदन, कत्या की लकड़ी इत्यादि जैसा अन्य प्रकार)
2. इन दिशानिर्देशों के पैरा-3 (ज) के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:-
राज्य स्तरीय समिति वन विभाग के क्षेत्रीय स्कन्ध से ऐसे किसी अधिकारी को जो वन संरक्षक से नीचे के स्तर का न हो तथा सम्बद्ध राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के कृषि विभाग और राजस्व विभाग से अधिकारियों को सहयोजित कर सकती है।
3. इन दिशानिर्देशों के पैरा-4 के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:—
राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) :—
- (i) जैसे और जब यह विनिश्चय करे, मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में समुचित अध्ययन के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलब्धता का निर्धारण करेगी। एसएलसी ऐसे तरीके से जो क्षेत्र के वनों को प्रतिकूलतः प्रभावित न करे, काष्ठ के बहनीय उपयोग के लिए समुचित तंत्र की प्रकल्पना करेगी।
- (ii) यदि एसएलसी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से काष्ठ उपलब्ध है (जैसे वन, वनों इत्यादि के बाहर वृक्ष) तो वह ऐसे काष्ठ आधारित उद्योगों के नामों का अनुमोदन करेगी, जिन पर नया लाइसेंस दिये जाने या विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।
- (iii) सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्य वन विभाग के पास रखी धन राशि (काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई) का उपयोग केवल वनीकरण के प्रयोजनार्थ किया जाए।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए किसी अन्य मामले की जांच करेगी और समुचित अनुशंसाएं करेगी।
4. इन दिशा निर्देशों के पैरा-5 के अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।
5. इन दिशा निर्देशों के पैरा-7 (ii) के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:
- (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा), निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के संबंध में, काष्ठ आधारित उद्योगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय/संबंधित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समिति के राज्य विशिष्ट आदेश/अनुमोदन के अनुसार प्रचालन की अनुमति दी जाएगी;

या, सड़क के किनारे/रिस्त्रे के किनारे/बंदर के किनारे के वृक्षारोपणों को छोड़कर निकटतम अभिसृष्टित बनी जलवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो।

(ख) काष्ठ आधारित उद्योग को निकटतम अभिसृष्टित वन क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी के लिए एक औद्योगिक संयंत्र जलवा एक समीचीन क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

6. इन दिशा निर्देशों के पैरा-8 के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

- किसी काष्ठ आधारित उद्योग को एसएलसी की पूर्वानुमति की प्राप्ति के बिना कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा जलवा नवीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, एसएलसी द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग को लाइसेंस के नवीकरण की शक्ति संबंधित वन प्रशासकीय वन अधिकारियों को प्रत्यापोजित की जा सकती है।
- निम्नलिखित उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जो घरेलू मूल के गोल सड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं या 30 सेंटीमीटर व्यास से अधिक के दंड आरा या री-साँ या शक्रीय आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगा।

ऐसे उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जिनमें निम्नलिखित का प्रयोग होता है:

- क. चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकड, प्लाइवुड, बेनियर या जामुन स्रोतों से प्राप्त आयातित लकड़ी
 - ख. ब्लॉक बोर्ड, एमडीएफ या जामुन स्रोतों से प्राप्त इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद
 - ग. कृषि-बानिकी/कृषिगत फसलों के रूप में घोषित प्रजातियां और/या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कटाई तथा पारंपरिक व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त और जामुन स्रोतों से प्राप्त गोल सड़/इमारती लकड़ी
- तथापि, संबंधित राज्य की एसएलसी द्वारा निश्चित किये जाने वाले ऐसे उद्योगों में 50 सेंटीमीटर तक व्यास के शक्रीय आरा को स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।

ऐसे उद्योग संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग से पंजीकृत और दियमित होंगे, जिनके लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विहित किए जाएंगे।

iii. बिक्रय/उत्तराधिकार इत्यादि की स्थिति में लाइसेंस का हस्तांतरण केवल एसएलसी के अनुमोदन से ही होगा।

7. इन दिशा निर्देशों के पैरा-9 (III) के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

यदि किसी कारण से अपील में इस प्रकार पारित आदेश द्वारा कोई व्यक्ति पोजित होता है तो वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में स्तुचित याचिका/आवेदन/अपील दाखल कर सकता है।

8. इन दिशा निर्देशों के पैरा-10 के अंतर्गत प्रविष्टियां का तोप किया जाता है।

9. इन दिशा निर्देशों के पैरा-11 (I) के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:—

प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग नियमित आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियंत्रित प्रपत्रों के अनुसार अभिसृष्टित का रखरखाव करेगा और अद्यतन करेगा।

10. दिशा-निर्देशों की जटिलता का लोप किया जाता है।

[भा. सं. 3-3/2015-एनए (सं. 10)]

नौमिन दाखलता, वन प्रशासकीय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Survey and Utilization Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th September, 2017

Subject: Amendment in Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016.

S.O. 3000(E).—In compliance of directions contained in the order dated October 5th, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavaram Thirumulpad versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India vide Resolution dated 11th November, 2016 had issued Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines,



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2693]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 2693]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ.3456(अ).— टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 के आदेश में निहित निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित दिशानिदेश बनाता है -

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ

(i) इन दिशानिदेशों को काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशानिदेश, 2016 कहा जाएगा।

(ii) ये दिशानिदेश समूचे भारत के लिए लागू होंगे।

(iii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने नियमों को इन दिशानिदेशों के अनुरूप बनाएंगे।

2. परिभाषा

(i) इन दिशानिदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'फर्नीचर इकाई' का अर्थ संयंत्र तथा मशीनरी और परिसर सहित इसका अहाता है जिसमें या जिसके किसी भाग में राउन्ड लॉग, जिसे एक अनुज्ञा पत्र धारी काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई या अन्य वैध स्रोतों से आउट सोर्स किया गया हो, को छोड़कर चिरी हुई लकड़ी, बेंत, वांस, नरकट, प्लाइवुड अथवा किसी अन्य काष्ठ आधारित का प्रयोग करके काष्ठ आधारित तैयार उत्पादों का निर्माण किया जाता है और जो किसी बेंड साँ अथवा री-साँ अथवा 30 सेंटीमीटर से अधिक व्यास के सरकुलर साँ के बिना परिचालित होता हो।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Survey and Utilization Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3456(E).—In compliance of directions contained in the Order dated October 5th, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is pleased to make the following guidelines, namely-

1. Short Title and commencement.

(i) These guidelines shall be called the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016

(ii) These shall extend to whole of India.

(iii) These shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

States/UTs shall conform their rules according to these guidelines.

2. Definition.

(i) In these guidelines, unless the context otherwise requires –

(a) 'Furniture unit' mean plants and machinery and the premises including the precincts thereof in which or in any part thereof wood based finished products are manufactured using sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood or any other wood based product, except a round log, outsourced from licensed wood based industrial units or other legitimate sources and operating without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter.

(b) 'Industrial Estate' means areas notified by the State Government or Union territory Administration for establishment of wood based industrial units.

(c) 'License' means a license granted under these guidelines.

(d) 'Principal Chief Conservator of Forests' means the Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) in the State and it will also include an officer designated as Head of Department in State/UT where no post in the rank of Principal Chief Conservator of Forests exists.

(e) 'Round log' means a piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimeter or more under bark and it will include such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment to make its cross section square or near to square for the purpose of ease in its transportation and or storage.

(f) 'Saw Mill', means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn sizes;

(g) 'Sawn Timber' means beams, scantlings, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log.

(h) 'State Level Committee' means a Committee Constituted by the State Government under para 3 (2) of these guidelines.

(i) 'Net Inter-State Import of a timber for Wood Based Industries' means three years moving average of the net quantity of such timber actually imported in the State during the latest three calendar years.

(j) 'Veneer Mill or Plywood Mill' means plants and machinery and the premises in which or in any part thereof, conversion into required size, slicing, peeling, fashioning or seasoning of timber/ wood, including preservation and treatment thereof either by mechanical or chemical process with the aid of electrical or mechanical power or manually is carried out.

(k) 'Wood Based Industry' means any industry which processes wood as its raw material (Saw mills/veneer/plywood/pulp or any other form such as sandal, katha wood etc.). It includes a mill but does not include a furniture unit.

(l) 'Year' means a financial year from 1st day of April to 31st day of March of the following year.

(ii) Words and expressions used but not defined under these guidelines and defined in the Indian Forest Act, 1927 or the relevant local Forest Act as applicable in a State, and the rules framed thereunder shall have the meaning assigned to them in such Act or Rules.

(iii) In case of any dispute regarding interpretation of any word or expression, the decision of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be final.

3. Constitution of the State Level Committee:

(i) Each State shall constitute a State Level Committee to perform the functions stipulated in these guidelines.

(ii) The State Level Committee shall consist of the following:

a)	Principal Chief Conservator of Forests/Head of Forest Department	Chairperson
b)	A representative of the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member
c)	A representative of the State Forest Department not below the rank of a Conservator of Forests dealing with preparation of Working Plans/Working Schemes	Member
d)	Director/Additional Director of Department of Industries	Member
e)	Representative of the each Autonomous District Council constituted in accordance with the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution, in case any such Council exists in the State	Member
f)	Representative of the Forest Development Corporation, in case any such Corporation exists in the State.	Member
g)	An officer not below the rank of Conservator of Forests working in the Forest Head Quarters	Member Secretary

(h) The State Level Committee may nominate any other officer working in territorial wing of the Forest Department not below the rank of CF.

(iii) Such State where the composition of State Level Committee already constituted is different from as stipulated in these guideline, shall, within one year from the date of publication of these guidelines, re-constitute the State Level Committee. The reconstitution of the State Level Committee will be without any prejudice to the recommendations made or the decisions taken by the existing State Level Committee till its re-constitution.

(iv) The State Level Committee shall meet at least once in three months.

(v) The quorum of the State Level Committee meeting shall be at least fifty percent of permanent members.

(vi) SLC will invite one representative of the industry nominated by the saw-mill association as a special invitee to each and every meeting of the State Level Committee.

4. Powers and functions of the State Level Committee.

The State Level Committee shall:-

(i) Assess the availability of timber for wood based industrial units in the State/UT every five years.

(ii) Assess quantity of different raw material requirement for wood based industrial units which may be sustainably harvested from trees outside forest areas in the State/UT.

(iii) Assess annual requirement of timber and other forest produce in the domestic markets in the State.

(iv) Maintain a database of timber and other raw materials utilized by each wood based industrial unit permitted to establish and operate in the State/UT during each financial year.

(v) Approve appropriate locations for setting up of wood based industrial units.

(vi) Approve the name of wood based industrial units which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity in case the committee is satisfied that timber is available legally for the said new Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests etc.).

(vii) The State Level Committee will ensure that the amount lying with the respective State Forest Departments (recovered from Wood Based Industries) will be utilized for the purpose of afforestation only.

(viii) Examine and make appropriate recommendations on any other matter referred by the State Government or the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

5. Assessment of the availability of timber for Wood Based Industrial Units:

(i) The quantity of timber likely to be available for utilization of Wood Based Industries of different types in a State/UT shall be assessed as by commissioning study, preferably in collaboration with institutes/ universities of repute, once in five years. The study will take into account the following:- :-

- (a) The quantity of such raw material that may be sustainably harvested from the forest areas as per the working plans/working schemes/ management plans duly approved by the competent authorities.
- (b) The quantity of such raw material that is available from the trees outside forest areas, including the private plantations, agro-forestry plantations and plantations raised on non-forest government lands *etc.*
- (c) Net inter-state import of such timber; and
- (d) Net international import of such timber.
6. **Estimated annual consumption of timber by wood based industries.** (i) For the purpose of assessing the timber requirement of the Saw mills, they may be divided into (a) Saw mills upto 10 HP (b) Saw mills between 10 and 20 HP (c) Saw mills between 20 HP to 40 HP (d) Saw mills between 40 to 60 HP and (e) Saw mills above 60 HP.

The annual requirement of round log for Saw mills of different capacities may be fixed by the committee based on the technical data or as per the formula given below

- (a) Saw mills of 10 HP and below: 540 cu.mt. (base value)
- (b) Saw mills between 10 to 20 HP: 810 cu.mt. (1.5 time the base value)
- (c) Saw mills between 20 to 40 HP 1080 cu.mt. (2 times of the base value)
- (d) Saw mills between 40 to 60 HP 1620 cu.mt. (3 times of the base value)
- (e) Saw mills above 60 HP 2160 cu.mt. (4 times the base value)

(ii) The Timber requirement for various units as assessed by Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Bangalore is given in **Annexure I**.

7. Restriction on location of wood based industries.

(i) In the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim the wood based industries shall be permitted to be established within the industrial estates.

(ii) In the States other than the afore-mentioned North Eastern States, wood based industries shall ordinarily be not allowed to be established within ten kilometers aerial distance from the boundary of nearest notified forests and protected areas. The State Level Committee for the reasons to be recorded in writing and after obtaining prior approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may permit to establish/operate a wood based industry at an aerial distance less than 10 kilometers from the boundary of a notified forest or a protected area.

8. Grant, renewal and revocation of a license to a wood based industry:

(i) No license to a wood based industrial unit shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the State Level Committee.

(ii) No wood based industrial unit shall be established/ operate in a State except under and in accordance with the license granted by an officer authorized by the State Government in this regard (Preferably DCF/DFO or equivalent).

(iii) The State Level Committee may maintain a separate list of wood based industries working solely on the timber imported from international market. The license to such industries shall specifically contain a condition to the effect that such units shall not be allowed to use timber produced in country. If in future, the said units want to use timber produced in the country on account of abundant availability they will seek specific permission from SLC to do so.

The SLC will ensure that the interests of the units using domestic produce are protected. Fresh licenses can be granted by the Committee for units which operate solely on imported raw material irrespective of the result of wood availability assessment in the State/UT.

(iv) The license granted to a wood based industry shall remain valid for five years, from the date of such issue or renewal of License. However, notwithstanding anything contained in these guidelines, the Licensing Authority may, where there are reasons to believe that the Licensee is operating the wood based industry in contravention of the provisions of these guidelines or conditions of License or any Rules framed by the State Government or is in activities prejudicial to the interest of forest conservation or public interest, at any time after giving one month notice, revoke the license granted to such wood based industry.

(v) Application for renewal of license granted to a wood based industrial unit shall be made at least three (3) months before the expiry of validity period.

(vi) Transfer of license on sale/succession etc shall be done only with the approval of State Level Committee.

9. Appeal against the decision of the State Level Committee.

(i) Any person aggrieved by any decision taken by the State Level Committee may file an appeal before the concerned Regional Office of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change seeking appropriate relief within 60 days' time.

(ii) Head of Regional Office shall within 60 days of filing the appeal pass the appropriate Order.

(iii) If, for any reason, any person is aggrieved by the orders so passed in the appeal, he may prefer an appropriate petition/application/appeal to the DGF&SS/MoEF&CC.

10. Conditions governing operation of furniture units.

(i) The Establishment and operation of a furniture unit shall not require a Licence.

(ii) A furniture unit:

(a) shall not use any band saw, or rip saw or a circular saw having more than thirty centimeter diameter

(b) shall not convert round logs

(c) shall use only sawn timber sourced from licensed sawn mills or any other legitimate source.

(d) In case the furniture unit is located within the premises of any wood based industry, approval of the Committee and the license for operation of furniture unit is required.

(e) may use bamboos, reeds and canes.

(f) shall maintain such records as may be stipulated by the State Forest Department.

11. Records to be maintained by wood based industries.

(i) Each wood based industry shall maintain and regularly update records as given in schedule to these guidelines.

[No.3-3/2015-SU (Vol.II)]

Dr. REKHA PAI, Inspector General of Forests

Annexure I**Assessment of Timber Requirement**

The Indian Plywood Industry Research and Training Institute (IPIRTI), Bangalore an autonomous body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has assessed the timber requirement per unit for peeling length of 4 feet and 8 feet size in the plywood/veneer units as 5 cu.mt. and 11 cu.mt. respectively per day on an average of 8 working hours per day. By assuming that the peeling units work for 8 hours per day on an average for 300 days in a year the normal timber requirement of the peeling length of 4 feet size in veneer units is 1500 cu.mt. The total timber requirement for the stand alone veneer units may be assessed by calculating the equivalent number of 4 feet length machines and by taking its normal installed capacity as 1500 cu.mt. per annum.

The timber requirement of a plywood unit may be taken as 'nil' on the ground that the round timber is used as timber in the veneer units only and that the plywood units are the secondary users which use the veneer as the raw material produced by the veneer units. The plywood units use presses of various sizes such as 8x4x6, 8x4x12, 8x4x15, 4x4x7, 4x4x10. A 8x4x10 capacity press can produce upto 10 plywood pieces of 8'x4' size per hour whereas a 8x4x15 capacity press can produce upto 15 plywood pieces of 8'x4' size per hour and so on. The normative installed capacity of the plywood units will accordingly depend upon the number and the type of presses. This number and type of presses installed in each of the plywood unit may be assessed and thereafter equivalent number or presses of 8x4x10 capacity may be calculated. The normative annual timber requirement for a integrated plywood unit having a 8 x 4 x 10 capacity press may be taken as 2000 cu.mt. per annum, and accordingly the total requirement of timber for the plywood units should be calculated.

SCHEDULE**PROFORMA -I (RECEIPT REGISTER)**

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood-Based Unit

Forest Division

Register Opened on

I(a)- RECEIPT REGISTER- TIMBER LOGS

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Serial No. of the log in the consignment (if given)	Species	Measurement (of each piece (s))			Remarks
		Issuing Authority	No.	Date			Length	Girth	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

I(b)- RECEIPT REGISTER – SAWN TIMBER

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Species	Measurement [of each piece (s)]				Remarks	
		Issuing Authority	No.	Date		No. of Pieces (if more than one piece is of same dimension)	Length	Width	Depth		Volume (in cum)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

I(c)- RECEIPT REGISTER – VENEER

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Brought from outside NE/ within NE	Whether Excise paid or otherwise (by the seller)	Species	Whether Face/Core	Measurement				Remarks
		Issuing Authority	No.	Date					Thickness (in mm)	Quantity in Sq. m.	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

I(d) - RECEIPT REGISTER – PLYWOOD, MDF, PARTICLE, BOARD etc

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass (if applicable) or carting Challan			Brought from outside NE/ within NE	Whether Excise paid or otherwise (by the seller)	Type of plywood, MDF, Particle Board	Measurement				Remarks
		Issuing Authority	No.	Date				Thickness (in mm)	Quantity in Sq. m.	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

PROFORMA –II (CONVERSION REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood –Based Unit

Forest Division

Register Opened on

II (a) - CONVERSION REGISTER-SAWN TIMBER

Date	Species	Round timber used		Sawn timber produced		Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs.	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II (b) - CONVERSION REGISTER- VENEER

Date	Species	Round Timber used		Sawn timber used (if any)		Whether Face/Core	Veneer Produced				Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)		Thickness in mm	Face area in sq. m	Notional area (with thickness as 4 mm) in sq. m.	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

II (c)
CONVERSION REGISTER- PLYWOOD/Blockboard

Date	Species	Round Timber used		Sawn timber used (if any)		Core Veneer used			Face veneer used			Production of plywood					Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)	Thick in mm	Face area in sq. m	Volume (in cum)	Thick in mm	Face area in sq. m	Volume (in cum)	Category	Thick	Face area in sq. m	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Note 1: In Proforma II (a) monthly species wise abstract of round timber used and total sawn timber produced is to be mentioned. In Proforma II (b) monthly species wise abstract of timber used, species wise and thickness wise core and face veneer produced is to be mentioned. In Proforma II (c) monthly species wise abstract of timber/sawn timber used species wise and thickness wise core and face veneer used and category wise plywood produced is to be mentioned.

Note 2: Six major commercial species for timber sawn timber and veneer are to be mentioned individually. The others may be clubbed under miscellaneous category. Exact categorization is to be decided by the Principal Chief Conservator of Forests.

Note 3: In column 8 of Proforma II (b) actual thickness of the veneer produced is to be given. In column No. 10 the national area is to be mentioned after calculating it with thickness as 4 mm.

Note 4: For partly used timber logs/sawn timber actual quantity of round timber/sawn timber used is to be mentioned in column 4 or 6 (as the case may be) and suitable entry to this effect is to be made in the Remarks column. While using the part used timber later on actual quantity now used is to be included in column 4/column 6. No corresponding entry towards no. of logs/sawn timber pcs. is to be made in column 3/column 5 and suitable explanatory entry in remark column is to be made.

Note 5: Only the proforma applicable for the particular unit is to be filled in For example. Saw Mill units are required to fill in only II (a) are not required to be filled in.

PROFORMA -III (DISPATCH REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

III (a): DISPATCH REGISTER- ROUND TIMBER

Date	Name & Address of the purchaser	Species	No. of Pcs.	Length	Girth	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
							No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

III (b): DISPATCH REGISTER- SAWN TIMBER

Date	Name & Address of the purchaser	Species	No. of Pcs.	Length	Width	Depth	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
								No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

III (c): DISPATCH REGISTER- VENEER

Date	Name & Address of the purchaser	Species	Excise Payable/ not payable Yes/ No	Whether Face/ Core	Thickness	Face Area in sq. m	National area (with thick as 4 mm) sq. m	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
									No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

III (d): DISPATCH REGISTER- PLYWOOD

Date	Name & Address of the purchaser	Type of Plywood	Excise Payable/ not payable Yes/ No	Whether Face/ Core	Thickness	Face Area in sq. m	National area (with thick as 4 mm) sq. m	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
									No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Note 1: Six major commercial species for timber, sawn timber and veneer are to be mentioned individually. The others may be clubbed under miscellaneous category. Exact categorization is to be decided by the Principal Chief Conservator of Forests.

Note 2: Only the proforma applicable for the particular unit is to be filled in. For example. Saw Mill units are required to fill in only III (a) & (b), III (c) & III (d) are not required to be filled in.

Note 3: In Column 6 of III (c) & III (d) actual thickness of Veneer/ plywood is to be mentioned.

PROFORMA -IV (CONVERSION REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood-Based Unit

Forest Division

Register Opened on

IV (a) STOCK REGISTER- ROUND TIMBER

Date	Species	Opening Stock		Received during the day		Used for sawing		Used for veneer/ Plywood making		Sold/ Returned in round form (dispatched outside the unit)		Closing stock		Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs.	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (b) STOCK REGISTER- ROUND TIMBER

Date	Species	Opening Stock		Received during the day (from outside the unit)		Converted from Round timber		Sold/ Returned in sawn		Used for veneer/ Plywood making (if any)		Closing stock		Remarks
		No. of Pcs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (c) STOCK REGISTER- VENEER

Date	Species	Opening Stock			Received during the day (from outside the unit)			Converted from Round/ Sawn timber			Veneer Sold/ Returned (dispatched outside the unit)			Used for Plywood making			Closing stock			Remarks	
		Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	

IV (d)

STOCK REGISTER- PLYWOOD

Date	Type of Ply-wood	Opening Stock			Received during the day (from outside the unit)			Converted from Veneer Round/ Sawn timber			Plywood Sold/ Returned/ dispatched outside the unit			Closing stock			Remarks	
		Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

- Note 1: Daily, weekly & monthly species wise abstract of opening stock, receipts, timber used for sawing, veneer/ plywood making, dispatched outside the unit and closing stock of sawn timber, veneer is to be recorded.
- Note 2: Six major commercial species for timber, sawn timber and veneer are to be mentioned individually. The others may be clubbed under miscellaneous category. Exact categorization is to be decided by the Principal Chief Conservator of Forests.
- Note 3: Only the proforma application for the particular units to be filled in for example. Saw Mills unit are required to fill in only IV (a) and IV (b), IV (c) and IV (d) are not required to be filled in.

પર્યાવરણ ,વન અને જલ વાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય

નવી દિલ્હી

ઠરાવ નં : એસ. ઓ. ૩૪૫૬(ઈ) તા. ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬

ભારત સરકાર નીચે જણાવેલ ગાઈડ લાઈન્સ બનાવે છે.

૧. ટાઈટલ

- (અ) આ ગાઈડ લાઈન વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ગાઈડ લાઈન્સ ૨૦૧૬ તરીકે કહેવાશે.
- (બ) સર્વે ભારત ને લાગુ પડશે.
- (ક) ઓફિસીયલ ગેઝેટમાં જે તારીખે પ્રકાશિત થશે ત્યારથી આ અમલમાં આવશે. આ ગાઈડ લાઈન ના આધારે રાજ્યો લાગુ પડતા નિયમો બનાવી શકશે.

૨. વ્યાખ્યા

- (ક) ફર્નીચર યુનિટ કોને કહેવાશે - વહેરેલ લાકડુ વાંસ, પ્લાયવુડ તેમજ અન્ય લાકડાની પેદાશો (સિવાય કે ગોળ લાકડુ)
- (ખ) ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ - રાજ્ય સરકારે નોટિફાય કરેલ વિસ્તાર.
- (ગ) લાયસન્સ - આ ગાઈડ લાઈન હેઠળ આપેલ લાયસન્સ.
- (ઘ) અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી - અધિકારીશ્રીઓના નામ
- (ચ) ગોળ લાકડુ- તેની વ્યાખ્યા- કુદરતી ફોરમમાં ૩૦ સેન્ટીમીટર કે તેનાથી વધુ ગર્થ ધરાવતુ લાકડુ.
- (છ) સોમીલ - વ્યાખ્યા ગોળ લાકડાને વહેરણ કામ કરનાર વિગેરે
- (જ) વહેરેલ લાકડુ - ગોળ લાકડુ વહેરીને બનાવેલ લાકડુ
- (ઝ) સ્ટેટ લેવલ કમિટિ - રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગાઈડ લાઈનના પેરા ૩ (૨) બનાવેલ કમિટિ.
- (ટ) વિનિયર / પ્લાયવુડ કોને કહેવાય -
- (ઠ) વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - તેની વ્યાખ્યા - સોમીલનો સમાવેશ થશે પરંતુ ફર્નીચર યુનિટ નહિ.
- (ડ) વર્ષ - ૧ એપ્રિલ થી ૩૧ મી માર્ચ સુધી

૩. સ્ટેટ લેવલ કમિટિ - ક્યા અધિકારીની બનશે તેની જાણકારી-

- (ક) જો સ્ટેટ લેવલ કમિટિ બનાવેલ હોય અને જુદી હોય તો નવી બનાવવાની રહેશે.
- (ખ) સ્ટેટ લેવલ કમિટિ ત્રણ મહિનામાં એક વખત મળશે.
- (ગ) ૫૦ ટકા જેટલા કાયમી મેમ્બર કોરમ ગણાશે.
- (ઘ) સ્ટેટ લેવલ કમિટિમાં સોમીલના એસોસીએશનના પ્રતિનિધિને આમંત્રિત કરાશે.

૪. સ્ટેટ લેવલ કમિટિની સત્તા અને કાર્ય શૈલી

- (ક) દર પાંચ વર્ષે વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ યુનિટ માટેની લાકડાની પ્રાપ્તિ અંગેની આકારણી.
- (ખ) વુડ બેઝ સ્થાપના માટેના યોગ્ય લોકેશનને મંજૂરી આપશે.
- (ગ) નવા લાયસન્સ અથવા લાયસન્સમાં ઉમેરો કરવા અંગેના વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામ મંજૂર કરશે.

૫. વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ યુનિટ માટેના લાકડાની પ્રાપ્તતા અંગેનું એસેસમેન્ટ અને તેના નિયમો.

૬. વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા અંદાજિત વાર્ષિક વપરાશ । ઉપયોગ

જુદી જુદી ક્ષમતા ધરાવતી સોમીલ માટેના ગોળ લાકડાની જરૂરિયાત ટેકનીકલ ડેટાને આધારે નક્કી કરે છે.

- (ક) ૧૦ હોર્ષ પાવર અને તેની નીચેના - ૫૪૦ ક્યુબિક મીટર
- (ખ) ૧૦ થી ૨૦ હોર્ષ પાવર ૮૧૦ ક્યુબિક મીટર
- (ગ) ૨૦ થી ૪૦ હોર્ષ પાવર ૧૦૮૦ ક્યુબીક મીટર
- (ઘ) ૪૦ થી ૬૦ હોર્ષ પાવર ૧૬૨૦ ક્યુબિક મીટર
- (ચ) ૬૦ થી વધુ હોર્ષ પાવર ૨૧૬૦ ક્યુબિક મીટર

.....૨.
(૫૧૬૧)

૭. વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ના લોકેશન માટેનું નિયંત્રણ
નક્કી કરેલ રાજ્યોમાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ સ્થાપવાની મંજૂરી મળશે.
આ સિવાયના સામાન્ય રીતે જંગલના નોટીફાઈડ વિસ્તારથી ૧૦ કલોમીટરની મર્યાદામાં મંજૂરી મળશે નહિ.
૮. વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના લાયસન્સની મંજૂરી, રીન્યુઅલ અને રદ બાતલ.
(ક) સ્ટેટ લેવલ કમિટિની પૂર્વ મંજૂરી વગર વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને લાયસન્સ ઈસ્યુ કરાશએ નહિ.
(ખ) લાયસન્સના ગ્રાન્ટ સિવાયની વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સ્થાપી શકાશે નહિ.
(ગ) આયાતી લાકડાનું વહેરણકામ કરતી વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સ્ટેટ લેવલ કમિટિ જૂદુ લીસ્ટ બનાવશે. - પારીવારિક ઉત્પાદન વાપરતી વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને રક્ષણ આપવામાં આવશે.
(ઘ) વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને આપેલ લાયસન્સ પાંચ વર્ષ માટે માન્ય રહેશે. છતાં વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ નિયમ વિરૂધ્ધની કાર્યવાહી કરતી માલુમ પડશે તો એક માસની નોટિસ આપ્યા બાદ લાયસન્સ રદ કરી શકાશે.
(ચ) લાયસન્સ માટે સમય પૂર્ણ થતાં પહેલાં ત્રણ માસ અગાઉ અરજી કરવાની રહેશે.
(છ) સ્ટેટ લેવલ કમિટિની મંજૂરીથી લાયસન્સ ટ્રાન્સફર / વેચાણ / હસ્તાંતર કરી શકાશે.
૯. સ્ટેટ લેવલ કમિટિના નિર્ણય સામે અપીલ
સ્ટેટ લેવલ કમિટિના નિર્ણય સામે કોઈ વાંધો હોય તો તે માટેની અપીલ અધિકૃત અધિકારી સામે કરી શકાશે. - ૬૦ દિવસમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે.
૧૦. ફર્નીચર યુનિટના ઓપરેશન માટેની શરતો.
(ક) જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ્સ સરકારે બનાવેલ છે.
(ખ) ટીમ્બર લોગ માટેનું આવક રજીસ્ટર અને જાવક રજીસ્ટર
(ગ) વહેરેલ લાકડા માટેનું આવક રજીસ્ટર અને જાવક રજીસ્ટર
(ઘ) વિનીયર માટેનું આવક રજીસ્ટર અને જાવક રજીસ્ટર
(ચ) પ્લાયવુડ / એમડીએફ / પાર્ટીકલ બોર્ડ વિગેરે માટેનું આવક રજીસ્ટર અને જાવક રજીસ્ટર
(છ) વહેરેલ લાકડાનું રૂપાંતર રજીસ્ટર
ઉપર જણાવેલ વિનીયર / પ્લાયવુડ / એમડીએફ / પાર્ટીકલ બોર્ડ રૂપાંતર રજીસ્ટર અલગ બનાવવાના રહેશે.

પર્યાવરણ ,વન અને જલ વાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય
નવી દિલ્હી

ઠરાવ નં : એસ. ઓ. ૩૦૦૦(એફ) તા. ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

વિષય: વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની ગાઈડ લાઈન્સમાં સુધારો

અગાઉના ટી.એન. ગોદાવર્મનના કેસમાં સુપ્રિમકોર્ટના આદેશને ધ્યાનમાં લઈ પર્યાવરણ અને વન વિભાગ દ્વારા તા.૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬ ના ઠરાવ અન્વયે વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (સ્થાપના અને નિયમન) અંગે ગાઈડ લાઈન ઈસ્યુ કરી છે. આ ગાઈડ લાઈન પર રાજ્ય સરકારે / રાજ્ય ક્ષેત્રો / અન્ય હિતકારે દ્વારા મળેલ સૂચનો / વિચારોને ધ્યાનમાં લઈ ભારત સરકારે ગાઈડ લાઈનમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેના ફેરફાર / સુધારા કરવા નિર્ણય કર્યો છે.

૧. ગાઈડ લાઈનની પેરા-૨(૧) હેઠળની ગાઈડ લાઈન નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે સુધારવામાં આવે છે.
 - (એ) ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય સરકાર / યુનિયન ટેરેટરી દ્વારા વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના માટે નોટિફાય કરેલ વિસ્તાર
 - (બી) લાયસન્સ એટલે કે સરકારની ગાઈડ લાઈન દ્વારા ઈસ્યુ કરેલ લાયસન્સ
 - (સી) પ્રી.સી.સી.એફ. એટલે આ ઠરાવમાં નક્કી કરેલ અધિકારી
 - (ડી) ગોળ લાકડુ એટલે કે ૩૦ સે.મી. થી વધુ ગર્થ ધરાવતુ કુદરતી અવસ્થામાંનો લાકડાનો ટુકડો.
 - (ઈ) સોમીલ ગોળ લાકડાને વહેરેલ લાકડામાં રૂપાંતર કરવાની જગ્યા.
 - (એફ) વહેરેલ લાકડુ એટલે બીમ સ્કેટલીંગ, પ્લેન્કસ, બેટન અને અન્ય એવી ગોળ લાકડામાંથી બનાવેલ વસ્તુઓ
 - (જી) સ્ટેટ લેવલ કમિટિ એટલે કે ગાઈડ લાઈન અનુસાર રચેલ કમિટિ
 - (એચ) વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે કોઈપણ ઈન્ડસ્ટ્રી જે લાકડાના કાચા માલને ચૉ મટીરીયલ્સ તરીકે પ્રોસેસ કરે છે.
૨. પેરા -૩ (બી) માં સમાવેશ કરેલ ગાઈડ લાઈન નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે સુધારવામાં આવે છે.

સ્ટેટ લેવલ કમિટિ વન વિભાગના સી.એફ. ના હોદ્દા કરતાં નીચેના નહિ અને એગ્રીકલ્ચર અને રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કો-ઓપ્ટ કરેલ અધિકારી.
૩. ગાઈડ લાઈનના પેરા - ૪ હેઠળની એન્ટ્રીઓ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે સુધારવામાં આવે છે.

સ્ટેટ લેવલ કમિટિ :

 ૧. ટીમ્બરની પ્રાપ્યતાનું એસેસમેન્ટ કરશે. એસ.એલ.સી. લાકડાનો ઉપયોગ જેનાથી ફોરેસ્ટ એરિયાને વિરૂધ્ધ અસર ન થાય તેવી યોજના ઘડશે.
 ૨. નવા લાયસન્સ આપવા માટે વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામને મંજૂરી આપશે, જ્યારે એસ.એલ.સી.ને સંતોષ થશે કે નવી વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના માટે લાકડુ પ્રાપ્ય છે.
 ૩. સ્ટેટ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે પડેલ લાકડુ ફક્ત વનીકરણના ઉપયોગ માટે કરશે તેવી ખાત્રી થાય.
 ૪. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પર્યાવરણ અંગેની રજૂઆતોને તપાસશે અને જરૂરી સુધારા સૂચવશે.
૪. ગાઈડ લાઈન્સની પેરા -૫ હેઠળની એન્ટ્રી રદ કરવામાં આવે છે.
૫. ગાઈડ લાઈન્સના પેરા- ૭ (૨) હેઠળની એન્ટ્રી નીચે પ્રમાણેની સુધારવામાં આવે છે.
 - (એ) રાજ્યમાં નોટિફાય કરેલ વન એરીયા અનુસારનું અંતર વિગેરે ધ્યાનમાં રાખી વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને ચલાવવા મંજૂરી આપશે.

.....૨.

- (બી) વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કઈ જગાએ સ્થાપી શકાશે તેનું સ્થળ નક્કી કરેલ છે.
૬. ગાઈડ લાઈના પેરા- ૮ હેઠળની એન્ટ્રીઓમાં નીચે પ્રમાણેના સુધારા :-
૧. સ્ટેટ લેવલ કમિટિની આગાઉ મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને કોઈ પણ લાયસન્સ ઈસ્યુ થશે નહિ. છતાં આવી સત્તા એસ.એલ.સી. વન વિભાગના અન્ય ડિવિઝનલ ફોરેસ્ટ ઓફિસરને આપી શકશે.
 ૨. છતાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેની ઈન્ડસ્ટ્રી જે ૩૦ સે.મી.ની ડાયા મીટરવાળી બેન્ડ સો મીલ જે ગોળ લાકડામાંથી રૂપાંતર કરતાં નથી તેને લાયસન્સની જરૂરિયાત રહેતી નથી.
એ. જે ઈન્ડસ્ટ્રીઝ / પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ જે ઉપયોગ કરે છે તેવું વહેરેલ લાકડુ, નેતર, વાંસ પ્લાયવુડ, વિનિયર.
બી. બ્લોકબોર્ડ, એમ.ડી.એફ. અથવા એવુ અન્ય લાકડુ જે યોગ્ય સ્ત્રોતમાંથી મેળવેલ છે.
સી. ગોલ લાકડુ જે યોગ્ય સ્ત્રોતમાંથી મેળવેલ છે છતાં રાજ્યની એસ.એલ.સી. કમિટિ ૬૦ સે.મી. ડાયામીટરવાળી સરક્યુલર સાં, ખાસ જરૂરિયાત હોય તો સ્થાપના માટે મંજૂરી આપી શકશે.
આવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ રાજ્ય અને વન વિભાગ સાથે રજીસ્ટર કરી શકાશે જેની વિગતો રાજ્ય સરકાર નક્કી કરશે.
 ૩. વેચાણથી અથવા ઉત્તરધીકારીને લાયસન્સ ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રક્રિયા એસ.એલ.સી.ની મંજૂરીથી જ કરી શકાશે.
૭. પેરા - ૯ (૩) ની ગાઈડ લાઈન્સમાં નીચે પ્રમાણેનો સુધારો કરવામાં આવે છે.
જો કોઈને કોઈ કારણસર ઈસ્યુ કરેલ ઓર્ડરથી બાધ હોય તો તે હાઈકોર્ટમાં પીટીશન કરી શકશે.
૮. પેરા - ૧૦ ની ગાઈડ લાઈન દૂર કરવામાં આવે છે.
૯. પેરા - ૧૧ (૧) હેઠળની ગાઈડ લાઈનમાં નીચે પ્રમાણેનો સુધારો કરવામાં આવે છે.
દરેક વુડ બેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ રાજ્ય સરકારના આદેશ અનુસારનું ફોર્મેટ પ્રમાણેનો અપ્ટુ ડેટ અને રેગ્યુલર રેકોર્ડ રાખશે.
૧૦. ગાઈડ લાઈનનું પરિશિષ્ટ રદ કરવામાં આવે છે.

સહી-

સૌમિત્રા દાસ ગુપ્તા

ઈન્સપેક્ટર જનરલ - ફોરેસ્ટ